

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति घोषणा के बाद की पत्रकार वार्ता का संशोधित
प्रतिलेख: 7 फरवरी, 2025 (शुक्रवार)

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिभागी:

श्री संजय मल्होत्रा - गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री एम. राजेश्वर राव - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री टी. रबी शंकर - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री स्वामीनाथन जे. - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

संचालक:

श्री पुनीत पंचोली - मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

पुनीत पंचोली:

नमस्कार। कैलेंडर वर्ष 2025 की इस पहली मौद्रिक नीति के बाद की पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हमारे साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर, श्री संजय मल्होत्रा, उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर और श्री स्वामीनाथन जे. उपस्थित हैं। हमारे साथ कार्यपालक निदेशक डॉ. ओ. पी. मल्ल और डॉ. राजीव रंजन तथा रिज़र्व बैंक के अन्य सहयोगी भी मौजूद हैं। शुरुआत में, परंपरा के अनुसार, मैं गवर्नर महोदय से अपने उद्घाटन वक्तव्य देने का अनुरोध करूंगा। इसके बाद, हम प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करेंगे। गवर्नर महोदय।

संजय मल्होत्रा:

नमस्कार, इस पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत है। मैंने अपना वक्तव्य पहले ही दे दिया है, जिसे हमने अपलोड भी कर दिया है और मुझे विश्वास है कि आपने उसे पहले ही पढ़ लिया होगा। मेरे पास जोड़ने के लिए और कुछ नहीं है। मौद्रिक नीति समिति का संकल्प, इसके पीछे का तर्क और हमारे द्वारा लाए गए कुछ अन्य अतिरिक्त उपाय वहां बहुत स्पष्ट रूप से संप्रेषित किए गए हैं। तो, मुझे लगता है कि हम सीधे प्रश्नोत्तर सत्र की ओर बढ़ सकते हैं; इससे आप सभी को अतिरिक्त प्रश्न पूछने के लिए अधिक समय मिलेगा। अतः हम सीधे प्रश्नोत्तर सत्र की शुरुआत कर सकते हैं।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। शुरुआत करने से ठीक पहले, हमेशा की तरह, कुछ घोषणाएं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपनी बारी का इंतजार करें और प्रति व्यक्ति केवल एक प्रश्न तक सीमित रहें, और यदि समय अनुमति दे, तो हम हमेशा दूसरे प्रश्न के लिए

वापस जा सकते हैं। आप गलियारे में माइक हाथ में लिए अपने सहयोगियों को देख सकते हैं। वे आपको माइक देंगे। कृपया माइक में बोलें ताकि बाहर के लोग भी आपको सुन सकें। सर, आज मीडिया के 27 प्रतिभागी उपस्थित हैं। और आपकी अनुमति से, मैं उनके नाम पुकारूंगा। मैं सीएनबीसी टीवी18 की लता से उनका प्रश्न पूछने का अनुरोध करता हूं।

लता वेंकटेश, सीएनबीसी टीवी18:

धन्यवाद, गवर्नर महोदय और उप गवर्नर महोदय। तो, मैं सबसे पहले भाषा के एक पहलू को स्पष्ट करना चाहती हूं और फिर अपना प्रश्न पूछूंगी। क्योंकि पैरा 7 में, जहां आप ब्याज दर में कटौती की घोषणा कर रहे हैं, आप कहते हैं कि एमपीसी मुद्रास्फीति के स्थायी संरेखण पर स्पष्ट रूप से केंद्रित है, जबकि विकास का समर्थन कर रही है। तो, पहले मुद्रास्फीति, फिर विकास। तुरंत अगले पैराग्राफ में, आप कह रहे हैं कि विकास-मुद्रास्फीति की गतिशीलता एमपीसी के लिए मुद्रास्फीति के संरेखण पर केंद्रित रहते हुए विकास का समर्थन करने के लिए एक नीतिगत स्थान खोलती है। तो, क्या हमें इसे जानबूझकर या संयोगवश पढ़ना चाहिए? मेरा प्रश्न यह है कि ब्याज दरों में कटौती आमतौर पर तब पारित की जाती है जब चलनिधि अधिशेष में हो। तो, क्या आपकी घोषित नीति अंतर-बैंक प्रणाली में चलनिधि को अधिशेष में रखने की होगी या केवल पर्याप्त?

संजय मल्होत्रा:

तो, मैं पहले आपके दूसरे प्रश्न पर आता हूं। मुझे लगता है कि इसका प्रयास हमारे द्वारा दिए गए वक्तव्य में भी किया गया था। और आपने पिछले कुछ महीनों में और उससे भी पहले देखा होगा कि रिजर्व बैंक का प्रयास जितनी चलनिधि की आवश्यकता हो, उतनी प्रदान करना रहा है। और जब हम चलनिधि की बात करते हैं, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में भी उल्लेख किया है, तो यह रातोंरात और स्थायी दोनों तरह की चलनिधि है। हमने कई कदम उठाए हैं। आप जानते हैं कि हमने शायद पहली बार एक नियमित, पूर्व-घोषित दैनिक रातोंरात रेपो दर संचालन शुरू किया है। तो, यह मुख्य रूप से सभी को यह आश्वासन देने के लिए था कि क्षणिक या रातोंरात चलनिधि के संबंध में यह खिड़की हमेशा उपलब्ध है। दीर्घकालिक स्थायी चलनिधि के लिए भी, हमने एक उपाय के रूप में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की है, जिनमें से कुछ पहले ही संचालन में लाए जा चुके हैं; 20,000 करोड़ रुपये के ओएमओ (खुले बाजार संचालन) पहले ही किए जा चुके हैं, बाद में एक और 40,000 करोड़ रुपये, आज, हम 50,000 करोड़ रुपये के लिए 56-दिन की वीआरआर (परिवर्ती रेपो दर) आयोजित करने जा रहे हैं। हम हमेशा सतर्क रहते हैं। हम फुर्तीले रहेंगे। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमें जिन चलनिधि आवश्यकताओं की आवश्यकता होगी, उन्हें प्रदान करने में हम बहुत सक्रिय रहेंगे। यह हमारे कार्यों में से एक है और हम इसे करेंगे। आपके पहले प्रश्न पर आते हुए, हर चीज, हर वक्तव्य, हर शब्द जो एमपीसी

के वक्तव्य में और विशेष रूप से संकल्प में उल्लिखित है, क्योंकि आप संकल्प की ओर इशारा कर रही थीं, बहुत ही सावधानीपूर्वक तैयार किया गया, सोचा-समझा और जानबूझकर किया गया है।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। अगला प्रश्न रॉयटर्स की स्वाति का होगा।

स्वाति भट्ट, रॉयटर्स:

बहुत-बहुत धन्यवाद, सर। सर, अगले वर्ष के लिए आपका विकास अनुमान 6.7% है। यह फिर से सरकार की दी गई सीमा (6.3% से 6.8%) के ऊपरी छोर पर है। और जैसा कि हमने पिछले वर्ष भी देखा, आरबीआई को वर्ष के अंत में अपना अनुमान कम करना पड़ा था। आप विकास को लेकर इतना आशान्वित क्यों है, विशेष रूप से जब आप कह रहे हैं कि आप तटस्थ इसलिए बने हुए हैं क्योंकि गर्मी की लहरों आदि के कारण मुद्रास्फीति के जोखिम फिर से बढ़ सकते हैं? तो, विकास को लेकर यह आशावाद किस आधार पर है? धन्यवाद।

संजय मल्होत्रा:

देखिए, हम सभी मानदंडों का बहुत नियमित रूप से विश्लेषण करते हैं, जिनमें उच्च आवृत्ति वाले संकेतक भी शामिल हैं। चाहे वह कृषि क्षेत्र हो, जहां जलाशयों के स्तर अच्छे हैं (और मैंने अपने एमपीसी वक्तव्य में इसका विस्तृत आकलन भी किया है, आप इसे देख सकते हैं कि वास्तविक कारण क्या हैं, वे सभी वहां दिए गए हैं)। समय की बचत के लिए, मैं संक्षेप में उनका उल्लेख कर रहा हूं, चाहे वह कृषि के संदर्भ में हो या उपभोग के संदर्भ में। अब, हाल ही में आपने नीलसन सर्वेक्षण देखा होगा, जिसमें उपभोग के आंकड़े 7% से अधिक रहे हैं, जो बहुत अच्छा संकेत है। और यह वही प्रकार या सीमा है जो हम व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रक्षेपित कर रहे हैं। इसी तरह, विनिर्माण गतिविधियां भी पटरी पर लौट रही हैं; हमें जो पीएमआई स्तर मिले हैं, वे काफी संतोषजनक रहे हैं। इसलिए, यह सब हमें इस बात का आशावाद देता है कि हम वही संख्या प्राप्त करेंगे जो हमने प्रक्षेपित की है। मैंने अपने वक्तव्य में यह भी उल्लेख किया है कि हम अपने मैक्रोइकोनॉमिक मॉडल, अपने तात्कालिक अनुमान(नाउकास्ट) और पूर्वानुमानों में लगातार सुधार करते रहेंगे ताकि यथासंभव सटीक संख्या प्रदान की जा सके। कृपया ध्यान रखें कि ये केवल पूर्वानुमान हैं; रोजमर्रा की स्थितियां बदलती रहती हैं और जैसा कि आप जानते हैं, लोग कहते हैं कि जैसे ही आपके तथ्य बदलते हैं, आपके विचार भी बदल जाते हैं। इसलिए, यह उसी के अधीन है। धन्यवाद।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। अब हम बिजनेस स्टैंडर्ड के मनोजित की ओर बढ़ते हैं।

मनोजित साहा, बिजनेस स्टैंडर्ड:

धन्यवाद, गवर्नर महोदय। क्या यह कहना उचित होगा कि इस समय वृद्धि, मुद्रास्फीति पर प्राथमिकता है? और विकास-मुद्रास्फीति की वर्तमान गतिशीलता को देखते हुए वास्तविक ब्याज दर क्या हो सकती है?

संजय मल्होत्रा:

देखिए, आरबीआई अधिनियम ने हमें एक बहुत ही स्पष्ट जनादेश दिया है। कुछ देशों में, जैसा कि आप जानते हैं, मूल्य स्थिरता और विकास—दोनों को हासिल करना एक स्पष्ट दोहरा उद्देश्य होता है। हमारे मामले में, प्राथमिक उद्देश्य मुद्रास्फीति अर्थात् मूल्य स्थिरता है—यह यह कहने का अर्थ नहीं है कि दूसरा उद्देश्य महत्वपूर्ण नहीं है—लेकिन विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता मूल्य स्थिरता की है। इसलिए, हम लगातार उस पर केंद्रित रहेंगे और इन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम मुद्रास्फीति को हमें दिए गए लक्ष्य के साथ संरेखित करने का प्रयास करेंगे, साथ ही विकास का समर्थन भी करेंगे। वर्तमान में, जैसा कि संकल्प में भी कहा गया है, हमें लगा है कि अब समय आ गया है कि हम विकास का अधिक समर्थन कर सकें क्योंकि मुद्रास्फीति कम हो रही है और इसके और कम होने की उम्मीद है। हालांकि, यह भी कहा गया है कि हम एक तटस्थ रवैया बनाए रखेंगे ताकि हम बदलती मैक्रोइकोनॉमिक स्थितियों के प्रति सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया दे सकें। धन्यवाद।

मनोजित साहा, बिजनेस स्टैंडर्ड:

आपके अनुसार, वर्तमान विकास और मुद्रास्फीति की गतिशीलता को देखते हुए वास्तविक ब्याज दर क्या होगी?

संजय मल्होत्रा:

देखिए, आज हम 6.25% (रेपो दर) पर हैं और मुद्रास्फीति 5.2% है। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति है। थोक मूल्य सूचकांक इससे कम है। तो, इससे आपको लगभग 1.5% या इतनी ही वास्तविक दर मिलती है। वर्तमान में स्थिति यही है।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। आगे बढ़ते हुए, अब ब्लूमबर्ग के अनूप का प्रश्न।

अनूप रॉय, ब्लूमबर्ग:

सर, फिर से मुद्रास्फीति के लक्ष्य पर आते हुए। हमारे पास 2% से 6% की मुद्रास्फीति बैंड है। आपके पास इस बैंड की सुविधा है। साथ ही, आपने लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य प्रणाली का उल्लेख किया है और साथ ही आपका मूल मध्यमकालिक लक्ष्य 4% है। तो, बस यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप तब भी सहज रहेंगे यदि मुद्रास्फीति 2% से 6% की सीमा के भीतर बनी रहती है, या आप यह देखना चाहेंगे कि मुद्रास्फीति स्थायी रूप से 4% के आसपास स्थिर हो जाए?

संजय मल्होत्रा:

अनूप रॉय, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। जब आप किसी परीक्षा में जाते हैं, और उस परीक्षा में अधिकतम अंक मान लीजिए 100 हैं और उत्तीर्णांक 40 हैं, तो आप किसकी आकांक्षा करते हैं? क्या आप केवल उत्तीर्ण होने की आकांक्षा करते हैं या बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की? खैर, कुछ लोग सिर्फ उत्तीर्ण होना पसंद कर सकते हैं। लेकिन आरबीआई में, हम हर मामले में शीर्ष पर रहना पसंद करते हैं।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। क्या मैं ईटी नाउ के अंकुर को बुला सकता हूँ?

अंकुर मिश्रा, ईटी नाउ:

जबकि आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए वृद्धि का अनुमान 6.3% से 6.8% है और आपने ऊपरी छोर को लिया है। जब मैंने मुख्य आर्थिक सलाहकार से यह प्रश्न पूछा कि क्या 7% से अधिक की वृद्धि की संभावना है, तो उन्होंने कहा, हाँ, यह संभव है। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके आकलन के अनुसार, क्या इसकी आशावादी संभावना है? और एक और प्रश्न, सर। ईसीएल (प्रत्याशित ऋणगत हानि) प्रावधान और परियोजना वित्तपोषण मानदंडों के संबंध में, आपने अपने वक्तव्य में शुरुआत में ही उल्लेख किया है, लेकिन आपने चरणबद्ध कार्यान्वयन की भी बात कही है। अब, क्या ये कार्यान्वयन अगले महीने से या 1 अप्रैल से होंगे, जैसा कि मसौदा मानदंडों के अनुसार था? अंतिम मानदंड अभी आने बाकी हैं। परियोजना वित्तपोषण मानदंडों में उल्लेख किया गया था कि इसे चालू वित्तीय वर्ष में 2% होना चाहिए और फिर वित्त वर्ष 2026 और 2027 में। इसी तरह, एलसीआर (चलनिधि कवरेज अनुपात) मानदंडों के लिए भी 1 अप्रैल 2025 की तारीख अनंतिम रूप से दी गई थी। मैं यह समझना चाहता हूँ कि हम यहां कहां खड़े हैं - क्या इसमें विलंब होने वाला है या ये लागू किए जाएंगे? धन्यवाद।

संजय मल्होत्रा:

आपका पहला प्रश्न - क्या 7% प्राप्त करने योग्य है? देखिए, इन प्रश्नों का उत्तर देना कठिन है, लेकिन फिर भी, मैं जोखिम उठाते हुए यह कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से, भारत 7% और उससे अधिक की वृद्धि दर प्राप्त कर सकता है। हमें इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आपके दूसरे प्रश्न पर आते हुए, जो कुछ दिशा-निर्देशों से संबंधित है जो हमने जारी किए हैं जैसे एलसीआर, ईसीएल, परियोजना वित्तपोषण मानदंड आदि, मैंने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम एक संतुलन बनाए रखेंगे। यह केवल स्थिरता के बारे में नहीं है, इसकी एक लागत भी आती है। हम उन लागतों के प्रति बहुत सजग रहेंगे जो इससे आती हैं, ताकि हम अपने संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकें। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ क्योंकि आपने विशेष रूप से एलसीआर के बारे में पूछा था और हमने वहाँ उल्लेख किया था कि हम पर्याप्त समय देंगे। मुझे नहीं लगता कि 31 मार्च 2025 पर्याप्त समय दे रहा है। इसलिए, निश्चित रूप से उन्हें कम से कम 31 मार्च 2026 से पहले लागू नहीं किया जाएगा। न्यूनतम समय सीमा यही होनी चाहिए। मसौदा विनियम परिचालित किए गए थे। हमें टिप्पणियाँ मिली हैं। हम उनकी जांच कर रहे हैं। हमें जांच करने में समय लगेगा। आप देखिए, चलनिधि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कृपया यह समझने का प्रयास करें कि हम यह क्यों कर रहे हैं। हम यह मुख्य रूप से इसलिए कर रहे हैं ताकि बैंकों पर 'रन' (भागदौड़/जमा निकासी का दबाव) न हो। आपने 2023 में देखा होगा कि कुछ अमेरिकी बैंकों पर रन हुआ था क्योंकि उनके पास ऐसे विनियम नहीं थे। अब, हमारे पास वे विनियम हैं। लेकिन क्या हमारे पास जो चलनिधि और प्रावधान हैं, वे पर्याप्त हैं या नहीं, और उन्हें लगातार सुधारने की आवश्यकता है। इसलिए हमने इन मसौदा विनियमों में कुछ जमाओं के मुकाबले अधिक चलनिधि रखने का प्रावधान किया था, जिनके बारे में हमें लगा कि शायद उन पर बहाव का जोखिम अधिक हो। साथ ही, अब अन्य हितधारकों से टिप्पणियाँ आई हैं कि कुछ अन्य जमाओं के लिए चलनिधि की आवश्यकता कम हो सकती है। इसलिए हम उसकी भी जांच कर रहे हैं। जैसे ही हम सभी सुझावों की जांच करने में सक्षम होंगे... और मैं यह जानकर बहुत प्रसन्न हूँ, रिजर्व बैंक आने के बाद कि हम यहाँ प्रभाव विश्लेषण करते हैं। तो यह प्रभाव विश्लेषण कुछ हद तक किया गया है, लेकिन अब जो सुझाव आए हैं, उनके साथ हम अपने अनुमानों और अपने प्रभाव विश्लेषण को संशोधित कर रहे हैं और हम एक समय सीमा देंगे कि एलसीआर की कब उम्मीद की जा सकती है। इसी तरह, अन्य दिशा-निर्देशों के लिए भी, हम पर्याप्त समय सीमा देंगे। आप निश्चित रहें कि उन्हें निश्चित रूप से 31 मार्च 2025 जितनी जल्दी लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि यह निश्चित रूप से पर्याप्त समय नहीं होगा। हम कोई व्यवधान पैदा नहीं करना चाहते। हम एक सुचारु संक्रमण सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।

लता वेंकटेश, सीएनबीसी-टीवी18:

मार्च 2026 तक नहीं?

मनोजित साहा, बिजनस स्टैंडर्ड:

बस स्पष्ट करने के लिए, आपने 31/3/2026 कहा या 31/3/2025?

संजय मल्होत्रा:

हां। हम बहुत स्पष्ट हैं। यह एक वर्ष से अधिक का समय है। बैंकों के लिए दो महीने से कम का समय बहुत कम है, हम इसे महसूस करते हैं और इसलिए, हम कम से कम 31 मार्च 2026 तक का समय देंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि इसे 31 मार्च 2026 को ही होना चाहिए। हम उसकी आकांक्षा करेंगे। लेकिन हम इसे बहुत सुचारु बनाना चाहते हैं और यह चरणबद्ध भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि सभी विनियम, सभी मानदंड पहले दिन से लागू हो जाएं, जो कि सबसे जल्दी 31 मार्च 2026 को होगा।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। अगला प्रश्न मनीकंट्रोल की हंसिनी का है।

हंसिनी कार्तिक, मनीकंट्रोल:

नमस्ते, सर। मैं विनियमों वाले इस हिस्से पर ही बनी रहूंगी। आपकी आज की भाषा यह भी इंगित करती है कि विनियम बनाने की प्रक्रिया में बहुत अधिक परामर्शी प्रक्रिया होगी। आपने एलसीआर पर स्पष्टता दी, लेकिन हमने जो देखा है, विशेष रूप से पिछले चार वर्षों में और अधिकतर पिछले डेढ़ वर्षों में, वह यह है कि कुछ बैंकों और एनबीएफसी को व्यवसाय के कुछ पहलुओं पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ा है। दो बड़े बैंक अभी भी प्रतिबंधात्मक व्यापारिक नीतियों से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप इस बात पर पुनर्विचार करेंगे कि आप बैंकों को लक्षित कैसे करना चाहते हैं या कुछ चूकों को सुधारने के लिए उनके साथ कैसे काम करना चाहते हैं? और स्पष्टीकरण के तौर पर, आपने एलसीआर का उल्लेख किया, लेकिन परियोजना वित्त और निवेश दिशा-निर्देशों के बारे में क्या जो बैंकों को अपनी सहायक कंपनियों आदि में लेने की अनुमति है? क्या आप उनमें विलंब करना चाहेंगे या उस पर भी विलंब का अनुरोध किया गया है? क्या आप उन प्रस्तावित नीतियों पर भी अनुकूल विचार करना चाहेंगे, सर?

संजय मल्होत्रा:

देखिए, ईसीएल केवल एक चर्चा पत्र था। यहां तक कि मसौदा भी बाहर नहीं आया है। इसलिए, ईसीएल दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए कोई समय सीमा नहीं है। इसी तरह, परियोजना वित्त के लिए, आप निश्चित रहें, मुझे लगता है कि उन्हें अधिक समय की आवश्यकता होगी, 31 मार्च 2026 सबसे जल्दी की तारीख है। इसके अलावा, उन्हें एक-दूसरे के संयोजन में देखा जाना चाहिए। ईसीएल और परियोजना वित्त के बीच कुछ मात्रा में ओवरलैप (दोहराव) है। इसलिए हम जांच कर रहे हैं, क्योंकि परियोजना वित्त के लिए मसौदा विनियम निश्चित रूप से प्रकाशित किए गए थे, टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं, सुझाव प्राप्त हुए हैं, हम उनकी जांच कर रहे हैं और हम कुछ ऐसे नियम लेकर आएंगे, मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो जनता के हितों, जमाकर्ताओं के हितों और वित्तीय स्थिरता (जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है) को संतुलित करें, और साथ ही बैंकों की चिंताओं को भी ध्यान में रखें - संसाधनों के कुशल उपयोग को ध्यान में रखते हुए। और आपके दूसरे प्रश्न पर, कुछ दो बैंक जिन पर हमने रोक एवं निषेध (सीज एंड डेसिस्ट) उपाय लगाए हैं। देखिए, ये उपाय बहुत सोच-विचार के बाद, गहन चिंतन के बाद और इन संस्थाओं को अवसर देने के बाद लिए जाते हैं। चाहे ये बैंक हों या अन्य, मैं किसी विशेष संस्था का संदर्भ नहीं दे रहा हूं, और ये अंतिम उपाय हैं। हम इनका बार-बार उपयोग नहीं करना चाहेंगे। यह अंतिम उपाय है जिसका उपयोग केवल अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जब सभी अन्य उपाय विफल हो चुके हों और ये फिर से जनता के हित में हों, और हम भविष्य में भी इस नीति को बनाए रखेंगे। धन्यवाद।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। अगला प्रश्न मिंट की गोपिका का होगा।

गोपिका गोपाकुमार, मिंट:

धन्यवाद, पुनीत। धन्यवाद, गवर्नर महोदय। मेरा प्रश्न मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान पर है। आपने इस वर्ष और अगले वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान बरकरार रखा है। लेकिन, क्या आपने पूर्वानुमान की गणना करते समय या उसे देखते हुए रुपये के अवमूल्यन के प्रभाव को ध्यान में रखा है? मेरा दूसरा प्रश्न मौद्रिक नीति के लिए नए उप गवर्नर की नियुक्ति के संबंध में है। हम इस नियुक्ति की कब तक उम्मीद कर सकते हैं?

संजय मल्होत्रा:

दूसरे प्रश्न के लिए, आपको सरकार से पूछना होगा, यह मेरे अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। आपके पहले प्रश्न के संदर्भ में - हाँ। हमारे सभी अनुमान बनाते समय रुपये-डॉलर की नवीनतम विनिमय दर को ध्यान में रखा गया था और हम विभिन्न संवेदनशीलता विश्लेषण

भी करते हैं। तो हाँ, आपके प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर यह है कि हाँ, हमारे अनुमान बनाते समय इसे निश्चित रूप से विचारा गया था।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। अब, मैं जी बिजनेस की एकता को आमंत्रित करता हूँ।

एकता सूरी, जी बिजनेस:

नमस्कार सर। सर, हमने आपके भाषण में धोखाधड़ी के संबंध में सुना कि आपने कहा है कि बैंकों का डोमेन नाम 'bank.in' होगा। लेकिन, यदि हम धोखाधड़ी की बात करें, तो ग्राहकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले, यदि कोई धोखाधड़ी की रिपोर्ट करता है, तो उन्हें अपना पैसा जल्दी वापस नहीं मिलता। दूसरा, सामान्य मोबाइल नंबरों से परेशान करने वाले कॉल किए जा रहे हैं। आपने कई बार कहा है कि आवास पर मिलने वाले ऋण के अतिरिक्त ऋण (होम टॉप-अप लोन) को पर्सनल लोन के रूप में विज्ञापित न करें, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। 1600-140 नंबरों के संबंध में भी, जैसा कि आपने कहा था, वे लेनदेन और विपणन के लिए होंगे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। तो, ऐसे परिदृश्य में क्या आरबीआई बैंकों पर कड़ी कार्रवाई करेगा ताकि ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके?

संजय मल्होत्रा:

निश्चित रूप से, यह हमारा पूर्ण प्रयास और प्रयत्न होगा कि हम अपने ग्राहकों और जनता को सभी बैंकिंग सेवाएं सबसे सुविधाजनक तरीके से प्रदान करें, चाहे वह बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित हो जैसा कि आपने उल्लेख किया, या यदि उन्हें परेशान करने वाले कॉल प्राप्त होते हों। हमें इस पर काम करने की आवश्यकता है कि उन्हें कैसे मार्गदर्शन दिया जाए और इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। इसे निश्चित रूप से ध्यान में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, आपने विस्तार से कई छोटी बातें पूछी हैं, जिनके लिए मैं अपने उप गवर्नर से अनुरोध करूंगा कि वे इसके बारे में आपको और अधिक बताएं क्योंकि हमने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं। संक्षेप में, मैं स्वामीनाथन जी और राजेश्वर राव जी से इसके बारे में और अधिक विस्तार से समझाने का अनुरोध करूंगा।

स्वामीनाथन जे.:

सर, बस उसकी पुष्टि करते हुए, हाँ, आपने उन उपायों का भी उल्लेख किया जो हम पहले ही कर चुके हैं। तो जहां तक विनियमित संस्थाओं का संबंध है, 140 या 1600 की कुछ श्रृंखलाओं का उपयोग करने के लिए निर्देश पहले से ही लागू हैं। हम उपभोक्ताओं को परेशान करने वाले या धोखाधड़ी वाले कॉल से दूर रहने के लिए शिक्षित करने के लिए कई

जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। जैसा कि विनियामक दृष्टिकोण से भी लागू किया गया है, अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करने का प्रावधान लागू है। पूर्ण जांच लंबित रहने पर हमें 'शैडो क्रेडिट' (आभासी जमा) देने का प्रावधान भी लागू है और जब हम स्थल पर निरीक्षण करते हैं, तो इसका पालन भी जांचा जाता है। लेकिन अक्सर, ऐसे परेशान करने वाले कॉल अविनियमित संस्थाओं, ऐप्स और प्लेटफार्मों से भी आते हैं। यह कुछ ऐसा है जिस पर केवल सरकार, विनियामक और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का सक्रिय सहयोग ही काम कर सकता है। लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसके प्रति हम सजग हैं और हम ग्राहक के हित की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे और जहां भी नुकसान हुआ है, वहां शीघ्र निवारण की दिशा में काम करना हमारा प्रयास होगा।

एकता सूरी, जी बिजनेस:

सर, मुझे पता है कि आपने बहुत सी बातें बताई हैं जो पहले से ही लागू हैं, लेकिन भले ही आरबीआई लगातार कहता रहे कि आपको यह करना है, बैंक नहीं सुनते। आज तक, बैंकों ने होम टॉप-अप ऋण को पर्सनल लोन के रूप में विज्ञापित किया है, यह कहते हुए कि ऋण लें, इसका उपयोग अपनी शादी के लिए करें, यात्रा के लिए करें, या जब आप ऋण लेने जाते हैं, तो वे बीमा या क्रेडिट कार्ड लेने पर जोर देते हैं; गलत बिक्री आम है। तो, इन मुद्दों पर कोई पर्यवेक्षी कार्रवाई होगी?

स्वामीनाथन जे.:

देखिए, आपने जिन दो-तीन मुद्दों का उल्लेख किया है, उनमें से प्रत्येक के लिए निश्चित रूप से ढांचा मौजूद है। अक्सर, जैसा कि गवर्नर महोदय ने भी उल्लेख किया, विनियमों के अनुरूप न होने वाले कई ऐसे व्यवहारों को हम संवाद के माध्यम से हल करते हैं। पर्यवेक्षी कार्रवाई जो सार्वजनिक होती है, वह केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में होती है जहां घिनौने उल्लंघन या सबसे असामान्य व्यवहार होता है। अन्यथा, अक्सर पर्यवेक्षक द्विपक्षीय आधार पर संस्थाओं के साथ संवाद करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि विनियामक दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए। तो यह हमारा प्रयास होगा। हो सकता है कि आप उन्हें मीडिया में न पढ़ पाएं, लेकिन जहां भी अनुपालन नहीं होता है, वार्षिक आधार पर और चल रहे आधार पर, हम संस्थाओं के साथ व्यवहार करते हैं और अक्सर समय के साथ उन सभी का अनुपालन किया जाता है।

एम. राजेश्वर राव:

उप गवर्नर स्वामीनाथन के कथन में जोड़ते हुए, टॉप-अप ऋण(अलग से ऋण) के संबंध में दिशा-निर्देश पहले से ही मौजूद हैं कि उनका अंतिम उपयोग क्या होना चाहिए। यदि इसे

विभिन्न उद्देश्यों के लिए दिया जाता है, तो इसे असुरक्षित ऋण माना जाएगा और बैंक द्वारा तदनुसार इसका निपटान किया जाना होगा। यह पहला बिंदु है। गलत बिक्री और जबरदस्ती बीमा कराने के संबंध में, आरबीआई के दिशा-निर्देश पहले से ही मौजूद हैं और हम इन दिशा-निर्देशों की व्यापक समीक्षा भी कर रहे हैं। हमें इस क्षेत्र पर—साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में बैंकों के आचरण पर—शीघ्र ही कुछ नए दिशा-निर्देश लाने का प्रयास करना चाहिए।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, महोदय। अब मैं अनुराग को अपना प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

अनुराग शाह, ईटी नाउ स्वदेश:

धन्यवाद पुनीत सर और धन्यवाद गवर्नर महोदय। जिस प्रकार आरबीआई ने कहा है कि बैंक बीमा कंपनियों या विभिन्न सहायक कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, तो निवेश से संबंधित दिशा-निर्देश कब तक प्रभाव में आएंगे? और क्या हम इसमें यह देखेंगे कि यदि कोई बड़ी बीमा कंपनी बैंकों में बहुसंख्यक हिस्सेदारी खरीदना चाहती है, तो क्या इसके लिए कोई प्रावधान है? और कुछ दिन पहले वित्त मंत्री ने भी बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से गलत बिक्री की चिंता व्यक्त की थी, आईआरडीएआई के अध्यक्ष ने भी विशेष रूप से बीमा से संबंधित इसी चिंता को व्यक्त किया है। क्या आरबीआई का डेटा भी इसका समर्थन करता है? इस पर आरबीआई का क्या मत है?

संजय मल्होत्रा:

जैसा कि डीजी स्वामिनाथन ने अभी आपको बताया कि हम गलत बिक्री के बिल्कुल भी विरुद्ध हैं। यदि ऐसा कोई भी मामला हमारे ध्यान में आता है, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको इस बात की 100% आश्वस्त होना चाहिए कि यदि गलत बिक्री के संबंध में किसी के खिलाफ कोई शिकायत आती है, तो रिजर्व बैंक उस बैंक या संस्था के खिलाफ कार्रवाई करेगा। कार्रवाई कैसे की जाएगी, जैसा कि उप गवर्नर स्वामीनाथन ने समझाया, यह ऐसा नहीं है कि हम बैंक को कहें कि हम आपका पंजीकरण रद्द कर रहे हैं या आपका लाइसेंस बंद कर रहे हैं—आप यह भी समझते होंगे। लेकिन हम इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हैं और यदि ऐसा कोई घटना घटती है तो हम इसे बहुत गंभीरता से लेंगे।

और आपका पहला प्रश्न यह था कि बैंकिंग कंपनियों ने अपने कितने सहायक उपक्रम, एनबीएफसी या बीमा कंपनियां बनाई हैं, तो इसके संबंध में हमने दिशा-निर्देश प्रकाशित किए हैं और उस पर कई सुझाव या टिप्पणियां आई हैं, जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हम सब कुछ विचार में ले रहे हैं और उनके सुझावों

को ध्यान में रखते हुए गहराई से अध्ययन करने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। मैं बस इतना कहूंगा कि यदि कोई कंपनी या बैंक किसी अलग सहायक उपक्रम के माध्यम से वही व्यवसाय करता है, तो हमें दो प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला, हितों का टकराव होगा क्योंकि यह वही कंपनी है तो व्यवसाय इस कंपनी में हो रहा है या दूसरी कंपनी में। और दूसरी समस्या यह है कि यहां नियामक मध्यस्थता होती है। बैंक एक अलग नियामक वातावरण में काम करते हैं और एनबीएफसी एक अलग नियामक वातावरण में काम करते हैं, इसलिए एनबीएफसी के जोखिम बैंकों पर नहीं आते। यही तर्क और कारण है कि हमने ये दिशा-निर्देश क्यों प्रकाशित किए हैं।

और हम यह भी जानते हैं कि कई कंपनियों और बैंकों के पास विरासत संबंधी मुद्दे हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही विभिन्न प्रकार के एनबीएफसी और सहायक उपक्रम बनाए हुए हैं, तो हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? चूंकि हमने ही उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी थी। इसलिए, सब कुछ पर विचार करने के बाद कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें जमाकर्ताओं की भलाई को बनाए रखना है, साथ ही हमें बैंकों और बैंक मालिकों के बारे में भी सोचना है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी आगे की कार्रवाई करेंगे।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। अगला प्रश्न एनडीटीवी प्रॉफिट के विश्वनाथ का होगा।

विश्वनाथ नायर, एनडीटीवी प्रॉफिट:

नमस्कार गवर्नर महोदय। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एनडीटीवी प्रॉफिट से विश्वनाथ हूँ। आपके भाषण में दो चीजें नए रूप में सामने आईं। पहली थी 'कम प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति', जिसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने ब्याज दर में कटौती की उम्मीद की थी, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित नहीं था कि यह कब तक चलेगी। तो, मैं आपसे यह समझना चाहता हूँ कि जब आप कहते हैं कि मौद्रिक नीति समिति का मानना है कि वर्तमान स्थिति में कम प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति उचित है, तो क्या यह केवल इस नीति तक सीमित है या हम अगली कुछ तिमाहियों की भी बात कर रहे हैं? और दूसरा भाग, जो इन नियामक कदमों के सिलसिले में सामने आया, वह है 'विनियमन की लागत', जिसके बारे में मैंने कभी आरबीआई को बात करते हुए नहीं सुना। कम से कम आरबीआई हमेशा विनियमन की आवश्यकता के बारे में बात करता रहा है, विनियमन की लागत के बारे में इतना नहीं। मैं आपसे यह समझना चाहता हूँ कि अब तक मेरे कई सहकर्मियों ने यह लिखा है कि आरबीआई एक 'बिना बहस वाला' या 'लौह मुट्ठी' प्रकार का विनियामक रहा है, क्या हम उस चेहरे को बदल रहे हैं?

संजय मल्होत्रा:

नहीं, मैं अतीत के बारे में आपसे बात नहीं कर सकता। यह मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं निर्णय सुनाऊं। लेकिन मैं निश्चित रूप से यह कहूंगा कि आरबीआई एक संस्था के रूप में वर्षों से उसे सौंपे गए जनादेश को निभाने में सक्षम रहा है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि 'विनियमन की लागत' शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। यह एक अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि पहले से, चाहे सचेतन रूप से या अवचेतन रूप से—मुझे लगता है कि सचेतन रूप से—यह निश्चित रूप से यह तय करने में एक कारक रहा होगा कि वे क्या करने जा रहे हैं। हो सकता है आपने इसे न सुना हो। यह एक अलग बात है, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन जो देखा जा सकता है, आरबीआई के बाहर रहकर और आरबीआई के साथ बातचीत करके, आरबीआई के बोर्ड में रहकर, ये सभी कारक निश्चित रूप से किसी भी विनियम बनाते समय विचार में लिए जाते हैं। तो, यह केवल वित्तीय स्थिरता के बारे में नहीं है, बल्कि उस लागत के बारे में भी है जिस पर ये चीजें आती हैं। मैंने इसे केवल इसलिए बहुत स्पष्ट किया ताकि सभी को इस बात का आश्वासन मिल सके। तो, यह एक बात हुई।

और दूसरा, आपने पूछा कि क्या यह नीति केवल इसके लिए है, तो जाहिर है, जब हम एक तटस्थ रुख अपनाए हुए हैं, और जैसा कि उल्लेख किया गया, इसके पीछे का तर्क यह है कि आज हम जिस भारी अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं, वह हमें अपना रुख बदलने के लिए नहीं कहती। हमारा रुख तटस्थ बना हुआ है। यह 'कम प्रतिबंधात्मक नीति' केवल इस विशेष एमपीसी बैठक के लिए है और भविष्य के लिए नहीं। यह रुख तटस्थ ही बना रहेगा। धन्यवाद।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। अगला प्रश्न फाइनेंशियल टाइम्स के क्रिस का होगा।

क्रिस के, फाइनेंशियल टाइम्स:

नमस्ते। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यह जानना चाहता था कि भविष्य में रुपये पर पड़ रहे हालिया दबाव को लेकर आप कितने चिंतित हैं, और क्या आप आयातित मुद्रास्फीति को लेकर भी चिंतित हैं?

संजय मल्होत्रा:

देखिए, सबसे पहले, वह दर जिस पर रुपया स्थिर होता है, वह मांग और आपूर्ति का कार्य है। दूसरा, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमें वास्तव में इसे नहीं देखना चाहिए, लेकिन

शायद यह हमारा काम है और इसलिए हम इसे करते हैं। हमें वास्तव में दिन-प्रतिदिन की अस्थिरता को नहीं देखना चाहिए। हमें दीर्घकालिक दर को देखना चाहिए और जब मैं यह कहता हूँ, तो मैं यह केवल रुपये के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य संपत्ति वर्गों के लिए भी कह रहा हूँ—चाहे वह सेंसेक्स हो या निफ्टी, चाहे वह सोने की कीमतें हों या संपत्ति की कीमतें। दिन-प्रतिदिन के उतार-चढ़ाव इतने महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। जैसा कि मैंने उल्लेख किया, यह निश्चित रूप से ब्याज दर में कटौती और हमारे द्वारा बनाए रखे गए रूख का निर्णय लेते समय ध्यान में लिया गया था। यह निश्चित रूप से विचारा गया था। यह एक बात मैं कहना चाहता हूँ, और दूसरी बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं, एक अवमूल्यित रुपया निश्चित रूप से मुद्रास्फीति पर दबाव डालता है, लेकिन साथ ही वैश्विक अनिश्चितताएं भी हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए अधिक चिंता का विषय वैश्विक अनिश्चितताएं हैं कि वे कैसे आकार लेती हैं। तो वैश्विक अनिश्चितताएं, भले ही आप जानते हों कि व्यापार युद्ध या टैरिफ व्यापार युद्ध नहीं किए जाने वाले थे, लेकिन केवल अनिश्चितता ही चिंताजनक है क्योंकि इसका विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसका निवेश निर्णयों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसका उपभोग व्यय निर्णयों पर सीधा प्रभाव पड़ता है जो स्थगित हो जाते हैं। तो, आइए इसे ध्यान में रखें कि डॉलर की बहुत सराहना और रुपये का अवमूल्यन वास्तव में इस अनिश्चितता से जुड़ा हुआ है। इसलिए, यह अनिश्चितता जो एक हद तक डॉलर के मजबूत होने और रुपये का अवमूल्यन होने का अंतर्निहित कारण है, विकास के लिए अच्छी नहीं है। और यह आयातित मुद्रास्फीति के लिए भी अच्छी नहीं है। तो यह ऐसा कुछ है जिसके प्रति हम सभी को सजग रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, सर। अगला प्रश्न द इन्फॉर्मिस्ट के सिद्धार्थ का होगा।

सिद्धार्थ उपासानी, द इन्फॉर्मिस्ट:

धन्यवाद, सर। नमस्कार गवर्नर महोदय।

संजय मल्होत्रा:

नमस्कार।

सिद्धार्थ उपासानी, द इन्फॉर्मिस्ट:

सर, मेरा प्रश्न चलनिधि पर है। हाल के वर्षों में सरकार के उच्च नकद शेष को देखते हुए, क्या चलनिधि प्रबंधन का आरबीआई का कार्य कठिन रहा है? वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में, डब्ल्यूएमए (अर्थोपाय अग्रिम सीमा को बढ़ाकर काफी मात्रा में 5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। आर्थिक कार्य सचिव ने यह भी कहा था कि सरकार कम नकदी की स्थिति

बनाए रखने का लक्ष्य रखेगी। और सचिव ने यह भी कहा कि वे कम नकदी की स्थिति बनाए रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन नकद धनराशि का बहुत कुछ हिस्सा राज्यों के अधिशेष और 14-दिनीय टी-बिल्स में उनके निवेश की ओर खींचा जाता है। मुझे लगता है कि वित्त वर्ष 2024 के अंत में यह 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक था। क्या सरकार और आरबीआई के बीच राज्यों को अधिशेष रखने से हतोत्साहित करने के लिए कुछ हो रहा है, शायद इन टी-बिल्स से ब्याज को और कम करें, या उन्हें अपने पैसे को बैंकों के साथ रखने की अनुमति दें? दूसरा, आपने आज हमारे सामने आने वाली भारी अनिश्चितताओं का उल्लेख किया, तो क्या यह आरबीआई के लिए जलन समिति द्वारा अनुशंसित 6.5% से अधिक आकस्मिक जोखिम बफर बढ़ाने का मामला बनाता है? धन्यवाद।

संजय मल्होत्रा:

कृपया अपना दूसरा प्रश्न पहले दोहराएं और फिर पहला प्रश्न। मैं इस पर उप गवर्नर राजेश्वर राव को उत्तर देने के लिए कहूंगा क्योंकि राज्य सरकारों के साथ कुछ संवाद हुआ है जिसके बारे में वे बेहतर जानते हैं, इसलिए वे उसका उत्तर देंगे, या श्री टी. रबी शंकर, वे आपके प्रश्न का उत्तर देंगे।

टी. रबी शंकर:

मैं इसका उत्तर दूंगा।

संजय मल्होत्रा:

आपके दूसरे प्रश्न पर आते हुए। देखिए, बिमल जालान समिति ने हमारे लिए तुलन पत्र का 5.5% से 6.5% का अनुपात बफर के रूप में बनाए रखने का सुझाव दिया था। 31 मार्च, 2024 को हम 6.5% पर हैं। यह समग्र ढांचा वर्तमान में समीक्षाधीन है। इसके आधार पर, यदि समिति को लगता है कि कोई बदलाव आवश्यक है, तो वह ऊपर की ओर भी हो सकता है या नीचे की ओर भी। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूँ कि अनिश्चितताओं के कारण इसे बढ़ाया जाना चाहिए; मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। यह प्रक्रियाधीन है और इसके आधार पर हम उस समिति की सिफारिशों के अनुसार निर्णय लेंगे जो इसकी समीक्षा कर रही है। आपके पहले प्रश्न के लिए, मैं श्री रबी शंकर से उत्तर देने का अनुरोध करता हूँ।

टी. रबी शंकर:

धन्यवाद, सर। मैं एक स्पष्टीकरण के साथ शुरू करूंगा। आप जिस ₹5 लाख करोड़ की संख्या का उल्लेख कर रहे हैं, वह संभवतः उपयोग से संबंधित है। प्रत्येक बार जब कुछ राशि निकाली जाती है, तो उसे संचयी रूप से जोड़ा जाता है। इसलिए यह सीमा का सही अनुमान नहीं देता है। सीमा वहीं बनी हुई है, जो पहले और दूसरे छमाही में काफी स्थिर

रही है और अब तक यह पर्याप्त रही है। हालांकि, यह देखते हुए कि सरकार की नकद स्थिति कैसे विकसित होती है, वर्ष की पहली और दूसरी छमाही के लिए आगे चलकर उन सीमाओं को तय किया जाएगा। कई कारणों से दैनिक आधार पर चलनिधि में अस्थायी बदलाव होते हैं, लेकिन बड़े बदलाव मुख्य रूप से सरकार के नकद शेष के कारण हुए हैं। इसलिए, दैनिक चलनिधि का प्रबंधन मूल रूप से सरकार के व्यय और राजस्व तथा इसके परिणामस्वरूप होने वाले नकद शेष के प्रभाव का प्रबंधन करना है। यह वह कार्य है जो हम करते हैं और जिसे हम दैनिक आधार पर जारी रखेंगे।

जहां तक यह प्रश्न है कि राज्य सरकारों का अधिशेष केंद्र सरकार के नकद शेष को कैसे प्रभावित करता है और इसलिए प्रणाली में चलनिधि पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह ऐसा विषय है जिसके प्रति हम राज्य सरकारों को हमेशा संवेदनशील बनाते हैं जब भी हम उनसे संवाद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम राज्य सरकारों के ऋण प्रबंधक भी हैं। हम उनसे नकद का यथासंभव कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। लेकिन दिन के अंत में, उनके व्यय के निर्णय उनके अपने निर्णय होते हैं और इसके परिणामस्वरूप जो नकद अधिशेष होता है, उसे प्रबंधित करने के लिए हमारे पास एक प्रणाली मौजूद है। इसमें से कुछ राशि गैर-प्रतिस्पर्धी खंड में नीलाम की जाने वाली ट्रेजरी बिल्लस में जाती है। कुछ राशि 'तदर्थ' तिजोरी बिल के रूप में जाती है। इसलिए, यह व्यवस्था ठीक से काम कर रही है, और हमारा मानना है कि आगे चलकर राज्य सरकारें भी अपनी चलनिधि का अधिक कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में सक्षम होंगी। धन्यवाद।

संजय मल्होत्रा:

मैं यहाँ यह जोड़ना चाहूंगा कि यह हमारा काम है। राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को अपनी चलनिधि का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना चाहिए (और कई ऐसा कर भी रही हैं), और हम जितना भी समर्थन दे सकते हैं, दे रहे हैं। लेकिन, हम यह नहीं देख रहे हैं कि चलनिधि सरकार द्वारा प्रदान की जाए। नहीं, उन्हें अपना काम करना होगा। उन्हें अपने नकद शेष का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना होगा, और इसे ध्यान में रखते हुए हम उतनी चलनिधि प्रदान करेंगे जितनी आवश्यक हो। हम यह नहीं देख रहे हैं कि सरकार वास्तव में वह चलनिधि प्रदान करे। यह उनका काम नहीं है। यह हमारा काम है और हम उस काम को जारी रखेंगे।

सिद्धार्थ उपासानी, द इनफॉर्मिस्ट:

बस पहले उत्तर से संबंधित एक स्पष्टीकरण। आपने कहा कि इसकी समीक्षा की जा रही है। क्या हमें यह नहीं पता कि आकस्मिक जोखिम बफर की समीक्षा की जाएगी?

संजय मल्होत्रा:

मुझे लगता है कि लगभग हर 5 साल में।

एम. राजेश्वर राव:

मुझे लगता है कि जलन समिति की सिफारिशें मार्च 2024 तक की अवधि (2019-2024) के लिए थीं। हम आंतरिक रूप से पूरी चीज की समीक्षा कर रहे हैं और यह देख रहे हैं कि क्या कोई बदलाव आवश्यक है आदि। फिर हम आंतरिक रूप से इसे उचित प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे और यदि हमें सरकार या बोर्ड के साथ संवाद करने की आवश्यकता होगी, तो हम इसे बाद के चरण में करेंगे। लेकिन आंतरिक समीक्षा चल रही है और प्रक्रिया में है।

सिद्धार्थ उपासानी, द इनफॉर्मिस्ट:

तो क्या यह संपूर्ण आर्थिक पूंजी ढांचा है जिसकी समीक्षा की जा रही है?

एम. राजेश्वर राव:

जी हाँ।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, महोदय। मैं इकनॉमिक टाइम्स की संगीता से अनुरोध करता हूँ।

संगीता मेहता, इकनॉमिक टाइम्स:

धन्यवाद, सर। सर, चूंकि ब्याज दर में कटौती से तुरंत गृह ऋण और बाह्य बेंचमार्क आधारित उधार दर से जुड़े सभी ऋणों की दरों में कमी आएगी, यह तो निश्चित है। आपके आकलन के अनुसार, जमा दरों और उधार दरों—विशेष रूप से एमसीएलआर और प्रणाली में अन्य दरों—में दर कटौती का संचरण कब तक होने की उम्मीद है?

संजय मल्होत्रा:

देखिए, इनमें से कई जमा दरें ऐसे जमाराशियों से संबंधित हैं जो पहले से ही मौजूद हैं और जिनकी दरें पहले से ही तय हैं। नई जमाराशियां जो आने वाली हैं, केवल उन्हीं के संदर्भ में ये बदलाव प्रभावी होंगे। इसलिए, स्पष्ट रूप से, कई जमाराशियां 5 वर्षीय हैं। इसलिए, जिन्होंने पहले से ही वे जमाराशियां रखी हैं, उनके लिए कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें कुछ समय लगेगा, जो जमा की अवधि और मौजूदा जमाराशियों की औसत अवधि पर निर्भर करेगा। हमारा प्रयास यह होगा कि हम जितना भी समर्थन और चलनिधि आवश्यक हो, प्रदान करें ताकि यह संचरण यथाशीघ्र हो सके। एमसीएलआर के संदर्भ में,

मुझे लगता है कि यह छह-माही आधार पर होता है। इसलिए, मुझे लगता है कि अधिकांश बैंक इसे जनवरी और जुलाई से प्रभावी करने के लिए जून और दिसंबर में करते होंगे। अतः, एमसीएलआर के लिए, मुझे लगता है कि अधिकांश बैंकों की नीति इसे 6 महीने में एक बार संशोधित करने की है। इसलिए, जून आते-आते कुछ संशोधन देखे जाने चाहिए।

संजय मल्होत्रा:

क्या आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? हां, कृपया।

स्वामीनाथन जे.:

मैं बस इस पर कुछ जोड़ना चाहता था। मूल रूप से, बाह्य बेंचमार्क लिंक दरें ऋण पुस्तक का लगभग 40% हिस्सा हैं, जिस पर हमें अधिक तत्काल प्रभाव दिखाई देगा। एमसीएलआर से जुड़ी पुस्तक, जो कि ईबीएलआर पुस्तक के लगभग बराबर है, उसके प्रभाव को सामने आने में आम तौर पर हमारे पिछले अनुभव के आधार पर लगभग दो तिमाहियां लगती हैं, क्योंकि पुनःनिर्धारित अवधियां अधिकांशतः 6 महीने की होती हैं। हालांकि, कुछ ऋण 3 महीने या 1 वर्ष के बेंचमार्क से भी जुड़े होते हैं। इसलिए, आम तौर पर, हमारा अनुभव यह है कि इसमें लगभग दो तिमाहियां लगती हैं। और जैसा कि गवर्नर ने स्पष्ट किया, मौजूदा जमाराशियों को अनुबंधित दर पर ही जारी रखना होगा। केवल नई जमाराशियों के लिए दरें बदलेंगी। इसलिए, जमा दरों तक मौद्रिक नीति के संचरण के संदर्भ में, इसमें फिर से कम से कम लगभग दो तिमाहियां लगती हैं। यह वह सामान्य प्रवृत्ति है जो हमने देखी है।

पुनीत पंचोलो:

धन्यवाद, महोदय। सर, आपकी अनुमति से, अंतिम तीन प्रश्न?

संजय मल्होत्रा:

हां।

पुनीत पंचोलो:

धन्यवाद, सर। अगला, मैं द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के बेन से अनुरोध करूंगा।

बेन जोस, न्यू इंडियन एक्सप्रेस:

धन्यवाद, गवर्नर महोदय। मेरा प्रश्न बजट में दी गई 1 लाख करोड़ रुपये की कर रियायतों के बारे में है। यदि यह वास्तव में उन उपभोक्ताओं तक पहुंचती है जो कर छूट सीमाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, और यदि यह वास्तव में उपभोग में परिवर्तित होती है, तो

मुद्रास्फीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? निश्चित रूप से, राजकोषीय दृष्टिकोण से बजट विस्तारवादी नहीं है। इससे आपका कार्य सरल हो जाता है। लेकिन उपभोग के दृष्टिकोण से, यदि उन 1 करोड़ या 50 लाख लाभार्थी मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों से हैं जहां उपभोग पिछड़ रहा है, तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है? क्या आपने इसे ध्यान में रखा है? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि लाभ 1 लाख करोड़ नहीं बल्कि अधिकतम 25,000 करोड़ रुपये हो सकता है? तो, क्या यह मौद्रिक नीति के लिए ध्यान में लेने लायक पर्याप्त बड़ा नहीं है, या आपने इसे देखा है और वर्तमान में उद्योग के लिए निर्णय लिया है?

संजय मल्होत्रा:

जैसा कि मैंने कहा, मौद्रिक नीति समिति ने अपना निर्णय लेते समय सभी कारकों पर विचार किया है। निश्चित रूप से, बजट की घोषणा की गई, वह सार्वजनिक हुआ, उसका विश्लेषण किया गया और रेपो दर में कटौती का निर्णय लेते समय इसे भी ध्यान में रखा गया। समग्र रूप से, मुझे लगता है कि यह एक उत्कृष्ट बजट है, न केवल विकास के दृष्टिकोण से बल्कि मैं यह भी कहूंगा कि मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण से भी। विशेष रूप से, जैसा कि आपने भी उल्लेख किया, घाटे को 4.5% की ग्लाइड पथ दर पर भी नहीं रोककर उसे 4.4% पर सीमित किया गया है।

और मुझे यह नोट करते हुए विशेष रूप से अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि कृषि क्षेत्र को इसमें प्राथमिक फोकस दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की बास्केट का लगभग 46% हिस्सा खाद्य पदार्थों का है। इससे न केवल विकास में मदद मिलेगी, बल्कि मध्यम से दीर्घावधि में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भी सहायता मिलेगी। विशेष रूप से, मैं आपका ध्यान सब्जियों और फलों से संबंधित कार्यक्रम की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। कृपया ध्यान रखें कि सब्जियों का सीपीआई में 6% और फलों का 2.9% योगदान है, जो कुल मिलाकर 8.9% होता है। खाद्य पदार्थों और विशेष रूप से फलों और सब्जियों के लिए एक योजना/कार्यक्रम लाया जा रहा है। मुझे लगता है कि फलों और सब्जियों से संबंधित मुद्रास्फीति ने निश्चित रूप से—मैं यह नहीं जानता कि उनकी सोच में क्या गया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसने—उनकी सोच में प्रभाव डाला होगा।

इसी तरह, मुझे यह नोट करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि दलहनों के लिए एक मिशन घोषित किया गया है। दलहनों का भार भी लगभग 2.5% या मेरी स्मृति सही है तो 2.4% है, और हाल के महीनों में हमने जो मुद्रास्फीति देखी है, उसमें दलहनों ने भी प्रमुख भूमिका निभाई है। दलहनों के लिए अब एक मिशन घोषित किया गया है। इसके अलावा, कृषि के लिए कई अन्य कार्यक्रम भी घोषित किए गए हैं।

यह 1 लाख करोड़ रुपये की कर राहत, मुझे लगता है कि इसकी बहुत अधिक इच्छा थी। हर कोई इसे चाहता था। अब जब यह मिल गई है, तो प्रति-प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, यह-वह और सब। मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न वास्तव में उचित हैं। और मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि इसका मुद्रास्फीति पर कोई ऊपर की ओर प्रभाव पड़ने वाला है। आज हमारे पास पर्याप्त उत्पादक क्षमता मौजूद है और क्षमता उपयोग स्तर 75% हैं। इस कर राहत से केवल हमारे विकास में मदद मिलेगी। और इसका मुद्रास्फीति पर कोई प्रमुख प्रभाव नहीं होना चाहिए।

बेन जोस, इंडियन एक्सप्रेस:

तो, क्या मुझे जलन समिति के आर्थिक पूंजी ढांचे पर एक स्पष्टीकरण मिल सकता है? जलन समिति एक बाहरी समिति थी जिसमें आरबीआई के सदस्य भी थे। लेकिन क्या आरबीआई इसे आंतरिक रूप से समीक्षित कर रहा है या कोई बाहरी समिति इसकी समीक्षा कर रही है?

संजय मल्होत्रा:

आंतरिक। यह एक आंतरिक समीक्षा है, जो किए जाने की आवश्यकता थी, जिसे हम करेंगे क्योंकि जैसा कि उप गवर्नर राजेश्वर राव ने उल्लेख किया, समय अवधि समाप्त हो गई है। इसलिए, इसकी समीक्षा होनी बाकी थी। अतः यह आंतरिक रूप से की जाएगी।

बेन जोस, इंडियन एक्सप्रेस:

धन्यवाद।

पुनीत पंचोलो:

धन्यवाद, सर। अगला, हमारे पास दूरदर्शन की श्यामा हैं।

श्यामा मिश्रा, दूरदर्शन:

नमस्ते सर। सर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या (अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड) ट्रंप का क्रिप्टो के प्रति समर्थक रवैया भारत को चिंतित करता है? और यदि हां, तो इसका सामना करने के लिए आरबीआई का दृष्टिकोण क्या होगा?

टी. रबि शंकर:

क्रिप्टो करेंसी पर आरबीआई की सोच बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त की जा चुकी है और उस सोच में कोई बदलाव नहीं आया है, क्योंकि वह सोच हमारी क्रिप्टो की समझ पर आधारित है। और क्रिप्टो के बारे में हमारी समझ इसलिए नहीं बदलेगी क्योंकि कुछ देशों ने इस पर

कुछ नीतियां अपनाई हैं। अतः, यह हमारा रवैया अपरिवर्तित बना हुआ है। यह कहते हुए भी, जैसा कि कुछ आपको पता हो सकता है, एक समूह यह देख रहा है कि देश का क्रिप्टोकॉर्सेसी के प्रति दृष्टिकोण क्या होगा। वह समूह अपनी सिफारिशें देगा, जिनके आधार पर सरकार द्वारा निर्णय लिए जाएंगे, और हम सभी उसका पालन करेंगे। धन्यवाद।

पुनीत पंचोलो:

धन्यवाद, सर। और अंतिम प्रश्न फाइनेंशियल एक्सप्रेस के सचिन कुमार के लिए होगा।

सचिन कुमार, फाइनेंशियल एक्सप्रेस:

शुभ अपराह्न, गवर्नर महोदय। 2023 में आरबीआई द्वारा अरक्षित ऋणों पर जोखिम भार बढ़ाने के बाद, व्यक्तिगत ऋणों की वृद्धि में महत्वपूर्ण कमी आई है। तो, क्या आरबीआई व्यक्तिगत ऋणों की वृद्धि में आई इस कमी से संतुष्ट है या और अधिक कमी की इच्छा है?

संजय मल्होत्रा:

मुझे लगता है कि संक्षिप्त उत्तर है हां, हम संतुष्ट हैं। मुझे नहीं लगता कि और अधिक कमी की शायद आवश्यकता है, लेकिन मैं महानिदेशकों में से किसी एक से अनुरोध करता हूं कि यदि वे कुछ जोड़ना चाहें।

स्वामीनाथन जे.:

मुझे लगता है कि आपने वह उत्तर पहले ही दे दिया है, बस इसके पीछे का तर्क देने के लिए। यह एक इच्छित प्रभाव था; विनियामक उपाय तब किए गए थे जब कुछ खंडों में असामान्य वृद्धि देखी गई थी। जैसा कि हमने अपेक्षा की थी, वर्तमान समय में वही खंड अतिरिक्त तनाव या चूक का सामना कर रहे हैं। अतः, उपाय अच्छी तरह से सोचे-समझे थे और उनका इच्छित प्रभाव हुआ है। और जैसा कि गवर्नर ने स्पष्ट किया, वर्तमान समय में यह कमी ठीक है। लेकिन एक विनियामक के रूप में, हम आने वाले आंकड़ों पर नजर रखते हैं और यदि स्थिति किसी उपाय की मांग करती है, तो हम भौतिकता और आनुपातिकता को ध्यान में रखते हुए उसे लेंगे। अन्यथा, वर्तमान समय में यह कमी अपेक्षित थी और यह उसी रेखा पर आगे बढ़ रही है।

सचिन कुमार, फाइनेंशियल एक्सप्रेस:

तो, क्या यह मानना उचित होगा कि अब बैंक इन खंडों में उच्च स्तर पर ऋण देना फिर से शुरू कर सकते हैं?

स्वामीनाथन जे.:

यह मुख्य रूप से वह व्यापार मॉडल है जिसे व्यावसायिक इकाइयां अपनाएंगी। किसी विशेष वृद्धि दर या उत्पाद-मिश्रण को निर्धारित करना हमारा उद्देश्य नहीं है। यह इकाई से इकाई में भिन्न होता है। और सुविज्ञ बोर्ड होते हैं जो प्रबंधन को यह मार्गदर्शन देते हैं कि उनकी वृद्धि की महत्वाकांक्षाएं क्या होनी चाहिए। हम केवल यह देखते हैं कि क्या वे अपने जोखिम उठाने की क्षमता के अनुरूप हैं, क्या प्रणाली में कोई अत्यधिक सक्रियता हो रही है या कोई संभावित जोखिम निर्माण हो रहा है, या किसी विशेष क्षेत्र में जोखिम संकेंद्रण दिखाई दे रहा है। वहीं हमें हस्तक्षेप करना होता है। अन्यथा, किसी मॉडल को निर्धारित करना हमारा उद्देश्य नहीं है।

और बस इस अवसर का उपयोग करते हुए, जैसा कि विश्वनाथ ने भी पूछा था, उसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। प्रत्येक उपाय का एक प्रभाव और लागत विश्लेषण होता है - जो हम करते हैं, और हम तदनुसार निर्णय लेते हैं। इसलिए, ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसा निर्धारित करेंगे जो आवश्यक न लगे।

संजय मल्होत्रा:

मुझे बस उसमें कुछ जोड़ने दें। देखिए, हमने ऋण देना बंद नहीं किया था। हमने बैंकों या विनियमित इकाइयों को ऋण देना बंद करने के लिए निर्देश नहीं दिए थे या अनिवार्य नहीं किया था। बिल्कुल नहीं। मेरा मानना है कि कोविड से पहले जोखिम भार 125% थे। कोविड के बाद उन्हें कम कर दिया गया था। जब हमने देखा कि अब पर्याप्त और शायद वांछनीय स्तर से अधिक ऋण वृद्धि हो रही है, तो जोखिम भार को वापस उसी स्तर पर लाया गया जो कोविड से पहले सामान्य समय में था। इसलिए, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ असामान्य किया हो। यह केवल उसे वापस उसी स्थिति में लाना है जो सामान्य समय में जोखिम भार था। धन्यवाद।

हंसिनी कार्तिक, मनीकंट्रोल:

सर, यदि मैं उसी से जुड़ा एक प्रश्न पूछ सकूँ? जबकि मैं समझती हूँ कि असुरक्षित ऋणों पर यह 125% सामान्यीकरण है, लेकिन एनबीएफसी के बारे में क्या, सर? क्योंकि एनबीएफसी द्वारा भी इस क्षेत्र में एकाग्रता को रोकने के लिए जोखिम भार में सक्रिय रूप से वृद्धि की गई थी। और आज जब हम वृद्धि-उन्मुख दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, और वे अंतिम छोर तक ऋण वितरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो क्या आप जोखिम भार और एनबीएफसी पर पुनर्विचार करेंगे? यहीं पर वृद्धि को वास्तव में चोट पहुंच रही है।

स्वामीनाथन जे.:

शायद मैं स्पष्टीकरण दे सकता हूँ, सर। मूल रूप से, उस विशेष खंड को पारस्परिक संबंधित जोखिम के निर्माण के कारण लाया गया था। देखिए, एनबीएफसी के मूल रूप से तीन प्रकार के संसाधन होते हैं - अपनी इक्विटी, उनके बाजार उधारी और फिर बैंक वित्त। बैंक वित्त, जो पहले 30% से कम हुआ करता था, बढ़कर उनके तुलनपत्र का लगभग 46-47% संसाधन बन गया था। तो, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, हमने देखा कि दो वित्तीय इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंधितता के परिणामस्वरूप जोखिम संकेंद्रण बढ़ रहा है। इसलिए, हमने कुछ अतिरिक्त जोखिम लागू किए ताकि उसमें कमी आए।

अब यदि आप इसे देखें, तो एनबीएफसी के संसाधन अब कमोबेश प्रत्येक का एक-तिहाई हिस्सा होने के रूप में वितरित हैं। इसलिए, इसका फिर से एक निश्चित उद्देश्य था, जो इस समय भी मान्य है। अतः, मुझे नहीं लगता कि इस समय इन उपायों की समीक्षा करने का कोई कारण है। लेकिन जैसा कि हमने स्पष्ट किया, हम किसी भी समय आने वाले आंकड़ों पर नजर रखेंगे। किसी विशेष प्रकार के ऋण या व्यापार को रोकना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उसे नियंत्रित (moderate) करना है। यही वह है जो हम करेंगे।

विश्वनाथ नायर, एनडीटीवी प्रॉफिट:

आपने नवंबर 2023 में जब जोखिम भार बढ़ाए गए थे, तब लघुवित्त कंपनियों को इससे बाहर रखा था। हाँ। देखिए, मैं बस यह समझना चाहता हूँ। तब से हमने इन लघुवित्त कंपनियों द्वारा काफी तनाव और अत्यधिक ओवरलीवरेजिंग(लौटाने की क्षमता से अधिक ऋण देना) देखा है, जिसका उल्लेख वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भी किया गया है। क्या इस संबंध में कोई विचार प्रक्रिया चल रही है? क्या आप कुछ कदम उठाने पर विचार करेंगे?

स्वामीनाथन जे.:

यदि आप उसी विनियामक निरीक्षण को पढ़ें जिसे हमने नवंबर 2023 में लागू किया था, तो हमने आवास ऋण, वाहन ऋण या शिक्षा ऋण जैसे विकास-उन्मुख खंडों को इससे बाहर रखा था। हमने किसी अतिरिक्त अनुपालन के बोझ से छोटे उधारकर्ताओं को भी मुक्त रखा था। अतः, वर्तमान समय में कोई अन्य उपाय विचाराधीन नहीं है। इस तनाव से निपटने के लिए, वैसे भी, ऐसे संस्थानों को नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए अन्य विधियां मौजूद हैं जहां कोई असामान्य आंकड़े देखे जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में कोई सकल-सावधानी उपाय हमारे विचाराधीन नहीं है।

पुनीत पंचोली:

धन्यवाद, महोदय। इसके साथ ही हम इस पत्रकार वार्ता को समाप्त करते हैं। मैं अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए गवर्नर महोदय और उप-गवर्नर महोदयों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं मीडिया के सभी मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि वे सभा कक्ष के पीछे बाईं ओर से बाहर की ओर प्रस्थान करें। आप सभी का धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।